निजी पूंजीगत व्यय 7 .7 लाख करोड़ पर

विनिर्माण और सेवा क्षेत्र ने निवेश वृद्धि को दी मजबूती

सीआईआई ने ईंधन शुल्क कटौती वापस लेने की मांग उठाई

नयी दिल्ली, 10 मई भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने रविवार को बताया कि भारत का निजी पूंजीगत व्यय सितंबर 2024 के 4.6 लाख करोड़ रुपये से बढक़र सितंबर 2025 में 67 प्रतिशत बढक़र 7.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो देश के निवेश चक्र में व्यापक और मजबूत पुनरुद्धार का अब तक का सबसे निर्णायक संकेत है.

सीआईआई ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान और उसके बाद के लिए उद्योग जगत के लिए पांच-सूत्रीय कार्ययोजना भी प्रस्तुत की है, जिसमें पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में मार्च में की गई कटौती को चरणबद्ध तरीके से वापस लेना भी शामिल है. इसके अलावा, उसने उद्योग द्वारा स्वैच्छिक ऊर्जा संरक्षण संधि, एमएसएमई भुगतान की 45-दिन की गारंटी, आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा के साथ गहरे आयात प्रतिस्थापन, तथा निजी पूंजीगत व्यय को अग्रिम रूप से बढ़ाने के साथ स्वैच्छिक मूल्य संयम और इंटर्नशिप में वृद्धि करने की सलाह दी है.

उद्योग संगठन ने करीब 1,200 कंपनियों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर बताया कि निजी क्षेत्र का निवेश - जिसे शुद्ध स्थायी परिसंपत्तियों और निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों में वार्षिक परिवर्तन के रूप में मापा गया - सितंबर 2025 में बढक़र 7.7 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह एक साल पहले के 4.6 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक है. इस वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र ने अग्रणी भूमिका निभाई और कुल निजी पूंजीगत व्यय का लगभग आधा, यानी 3.8 लाख करोड़ रुपये का योगदान दिया. इसमें धातु, ऑटोमोबाइल और रसायन क्षेत्र सबसे आगे रहे.

देशभर में लागू हुए नए लेबर कोड

नयी दिल्ली, 10 मई. भारत में नए लेबर कोड्स अब पूरी तरह से लागू हो गए हैं, जिससे काम से जुड़े नियम अब कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए सरल और स्पष्ट हो गए हैं. पहले देश में 29 अलग-अलग श्रम कानून थे, जो जटिल और पालन में मुश्किल थे. इन नए चार कानूनों के लागू होने से वे सभी पुराने कानून समाप्त हो गए हैं. अब मजदूरों और नियोक्ताओं को नियम समझने और लागू करने में आसानी होगी. नई व्यवस्था के तहत, महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, जिससे लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा. महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद 26 हफ्ते की मातृत्व छुट्टी मिलेगी और आवश्यकता पड़ने पर घर से काम करने की सुविधा भी मिलेगी.

एफपीआई की बिकवाली जारी

मई के पहले सप्ताह में पूंजी बाजार से निकाले 9,772 करोड़ रुपये

मुंबई, 10 मई विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) ने मई के पहले कारोबारी सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार से 9,772 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है.

इससे पहले अप्रैल और मार्च में भी एफपीआई शुद्ध रूप से बिकवाल रहे थे, यानी उन्होंने जितना निवेश किया था उससे अधिक पैसे निकाले थे.

केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने मई में अबतक इक्विटी में 14,231 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है. हाइब्रिड उपकरणों में भी उनका निवेश ऋणात्मक रहा है जबकि डेट और म्यूचुअल फंड में उन्होंने पैसा लगाया है.

इस महीने डेट में एफपीआई का शुद्ध निवेश 4,384 करोड़ रुपये बढ़ा है. म्यूचुअल फंड में उन्होंने 187.72 करोड़ रुपये का निवेश किया. हाइब्रिड उपकरणों से उन्होंने 112.28 करोड़ रुपये निकाले.

यह लगातार तीसरा महीना है जब एफपीआई भारतीय पूंजी बाजार में बिकवाल बने हुए हैं. इस साल मार्च में उन्होंने 1,26,991 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिकवाली की थी. अप्रैल में भी उन्होंने 70,786 करोड़ रुपये निकाले थे. इस साल अब तक एफपीआई भारतीय पूंजी बाजार से शुद्ध रूप से 1,98,773 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं.

महंगाई के आंकड़ों से तय होगी बाजार की दिशा

मुंबई, 10 मई . घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह रही तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में महंगाई के आंकड़े निवेशकों की धारणा को दिशा देंगे. अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में यदि कोई विशेष प्रगति होती है तो उसका असर सीधे तौर पर बाजार पर पड़ेगा.

इसके अलावा, अगले सप्ताह खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़े भी जारी होने हैं. इनका असर भी बाजार पर दिखेगा. पिछले सप्ताह बीएसई का सेंसेक्स 414.69 अंक (0.54 प्रतिशत) की साप्ताहिक तेजी के साथ 77,328.19 अंक पर बंद हुआ. सूचकांक में सोमवार और बुधवार को तेजी रही जबकि अन्य तीन दिन गिरावट के रहे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 178.60 अंक (यानी 0.74 प्रतिशत) की साप्ताहिक तेजी के साथ 24,176.15 अंक पर पहुंच गया.

मझौली और छोटी कंपनियों के लिए यह सप्ताह अच्छी लिवाली वाला रहा. सप्ताह के दौरान निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 4.42 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 4.05 प्रतिशत उछल गया.

आलोच्य सप्ताह में सेंसेक्स की 30 से 20 कंपनियों के शेयर हरे निशान में रहे. महिंद्रा एंड महिंद्रा में 7.51 प्रतिशत की साप्ताहिक तेजी रही. एशियन पेंट्स का शेयर 6.37 प्रतिशत, अडानी पोर्ट्स का 6.35, इंडिगो का 5.27, बजाज फिनसर्व का 3.97, इटरनल का 3.87, अल्ट्राटेक सीमेंट का 3.15 और मारुति सुजुकी का 3.10 प्रतिशत चढ़ा.

चावल में साप्ताहिक नरमी गेहूं, चीनी महंगी

नयी दिल्ली, 10 मई . घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव टूट गये. वहीं, गेहूं और चीनी में तेजी का रुख रहा जबकि खाद्य तेलों और दालों में उतार-चढ़ाव देखा गया. सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 76 रुपये घटकर सप्ताहांत पर 3,761 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी. गेहूं तीन रुपये महंगा हुआ और 2,785 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया. आटे का भाव भी 17 रुपये बढ़कर 3,290 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया. सप्ताह के दौरान तुअर दाल की औसत कीमत 53 रुपये प्रति क्विंटल फिसल गयी. मूंग दाल में 26 रुपये और चना दाल में 18 रुपये की साप्ताहिक गिरावट रही. वहीं, उड़द दाल तीन रुपये और मसूर दाल दो रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई.

रिजर्व बैंक अधिकारियों ने नीति विरोध जताया

भारतीय रिजर्व बैंक के करीब 8,000 अधिकारियों ने नई प्रमोशन नीति के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया

मुंबई, 10 मई. भारतीय रिजर्व बैंक के करीब 8,000 अधिकारियों ने नई प्रमोशन नीति के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है. अधिकारियों का आरोप है कि समयबद्ध प्रमोशन प्रणाली को खत्म कर नई नीति में पदोन्नति को केवल रिक्तियों की उपलब्धता से जोड़ दिया गया है, जिससे खासकर युवा अधिकारियों का करियर प्रभावित हो रहा है.

अधिकारियों का कहना है कि इससे उनके मनोबल पर बुरा असर पड़ा है और कई कर्मियों को लंबे समय तक एक ही पद पर काम करना पड़ रहा है. 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन' ने इस मामले में गवर्नर संजय मल्होत्रा को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. पत्र में अधिकारियों ने बताया कि मैनेजमेंट ने उनकी आपत्तियों और सुझावों को ध्यान में रखे बिना नई नीति लागू कर दी. एसोसिएशन का यह भी कहना है कि पहले हुई बैठकों में गवर्नर ने समयबद्ध प्रमोशन के संकेत दिए थे, लेकिन अंतिम नीति में इसे शामिल नहीं किया गया. अधिकारियों ने प्रदर्शन में प्रमुख मांगों के रूप में यह उठाया है कि नई नीति को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, अधिकारी संगठन के साथ मिलकर नीति की व्यापक समीक्षा की जाए और एक निष्पक्ष तथा टिकाऊ प्रमोशन ढांचा तैयार किया जाए.

क्षेत्रीय कार्यालयों और मुंबई मुख्यालय में अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं. संगठन ने इस मामले में मैनेजमेंट से आग्रह किया है कि वे कर्मचारियों की चिंता को समझें और करियर ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध प्रमोशन प्रणाली को फिर से लागू करने पर विचार करें. यदि नई नीति को जल्द संशोधित नहीं किया गया, तो बैंक की कार्यक्षमता और कर्मचारी संतुष्टि दोनों पर दीर्घकालिक असर पड़ सकता है. अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि केवल पद रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर प्रमोशन व्यवस्था युवा अधिकारियों को हतोत्साहित कर रही है और भविष्य में प्रतिभाशाली कर्मियों के बैंक में बने रहने की संभावना को भी प्रभावित कर सकती है.

पेंशन योजनाओं के 11 साल पूरे, लोकप्रियता बढ़ी

नयी दिल्ली, 10 मई मोदी सरकार की आम जन को बीमा और पेंशन सुरक्षा देने के लिए शुरू की गयी तीन जन सुरक्षा योजनाओं - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएस बीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने 11 साल पूरे कर लिये है और इनको अपनाने वालों का आधार व्यापक हुआ है.

इन योजनाओं के 11 साल पूरे होने पर शनिवार को वित्त मंत्रालय की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार पीएमजेजेबीवाई के तहत कुल नामांकन 27.43 करोड़ से अधिक हो चुके हैं और 29.04.2026 तक 21,512.50 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इसी दौरान पीएमएस बीवाई के तहत कुल नामांकन 58.09 करोड़ से अधिक हो चुके हैं और 1,84,662 दावों के लिए 3,667.52 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इन 11 वर्षों में 9.04 करोड़ से अधिक लोगों ने एपीवाई योजना में नामांकन कराया है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन तीनों योजनाओं के आज 11 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पर कहा कि ये योजनाएं देश के नागरिकों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. उन्होंने अपने संदेश में कहा, 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ने जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं और देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की है.' उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना ने अनेक लोगों को अपनी वृद्धावस्था में अधिक सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम बनाया है. उन्होंने अटल पेंशन योजना के तहत महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और उन्हें मिल रहे लाभों पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने इस योजना की सफलता में 'नारी शक्ति' के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया.

श्रीमती सीतारमण ने जनता के बीच इन योजनाओं की बढती लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत क्रमश: 27 करोड़, 58 करोड़ और 9 करोड़ से अधिक नामांकन हुए हैं. उन्होंने कहा 'जन सुरक्षा योजनाओं की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर, बैंकों और बीमा कंपनियों के जमीनी स्तर के कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के प्रति हार्दिक आभार, जिनके समर्पित प्रयासों से ये योजनाएं इतनी सफल हुई.'

तेल संकट से बढ़ेगी भारत की महंगाई

कच्चा तेल 96 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान

नयी दिल्ली, 10 मई. पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है. एशियाई विकास बैंक ने आशंका जताई है कि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं, जिससे भारत में महंगाई और आर्थिक दबाव दोनों बढ़ेंगे.

एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क के अनुसार, वर्ष 2026 में कच्चे तेल की औसत कीमत 96 डॉलर प्रति बैरल तक रह सकती है, जबकि 2027 में इसके 80 डॉलर प्रति बैरल पर आने का अनुमान है.

भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयातित तेल और गैस से पूरा करता है. ऐसे में तेल कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर परिवहन, बिजली, उत्पादन और रोजमर्रा की वस्तुओं की लागत पर पड़ेगा. एडीबी ने अनुमान लगाया है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 0.6 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है.

सोना और चांदी के दामों में हल्की गिरावट

नई दिल्ली, 10 मई. भारत में आज सोने और चांदी के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार शुद्ध सोने की कीमत में लगभग 419 प्रति 10 ग्राम की कमी आई है और प्योर गोल्ड का भाव 167,623 पर आ गया है. 24 कैरेट सोना 166,952, 22 कैरेट 153,807 और 18 कैरेट सोना 125,843 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं चांदी की कीमत में भी नरमी देखी गई. आज 1 किलो चांदी रु. 97,872 पर रही, जो कल की तुलना में रु. 245 सस्ती हुई है.

गलत आईटीआर फॉर्म पर आ सकता है नोटिस

नई दिल्ली, 10 मई. इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने का समय शुरू हो गया है. इस दौरान सबसे जरूरी काम सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना है. अगर टैक्सपेयर्स गलत फॉर्म भर देते हैं तो उनका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है या फिर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भी आ सकता है. इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार सही फॉर्म चुनकर ही रिटर्न भरना चाहिए.

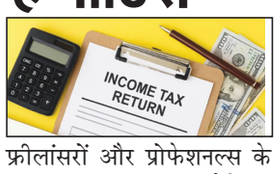

नौकरी करने वाले लोगों, फ्रीलांसरों और प्रोफेशनल्स के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म तय किए गए हैं. अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और वह नौकरी करता है तो उसे आईटीआर-1 (सहज) भरना होता है. इसमें वेतन, दो घर से होने वाली आय और बैंक ब्याज से होने वाली आय शामिल की जा सकती है.

समाचार विशेष

उत्तराखंड चुनाव में भी मुखर रहेगा सनातन मुद्दा

देहरादून. बंगाल और असम में मिली प्रचंड जीत के बाद यह तय माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी अगले विधानसभा चुनाव में सनातन के मुद्दे पर भाजपा मुखर रहने जा रही है. सनातन आस्था से जुड़े चारधाम स्थल और उनसे जुड़े विधानसभा क्षेत्रों पर कब्जे के लिए सत्ताधारी दल ने विशेष रूप से योजना बनाई है.

विशेष रूप से केदारनाथ और बदरीनाथ विधानसभा क्षेत्रों को केंद्र में रखकर व्यूह रचना बनाई जा रही है. अभी केदारनाथ सीट भाजपा तो बदरीनाथ सीट पर कांग्रेस का कब्जा है. अगले चुनाव में इन दोनों सीट को जीतकर पार्टी पूरे देश में संदेश देने की तैयारी में है. देवभूमि उत्तराखंड में सनातन आस्था से गहरे जुड़े चारधाम तो हैं ही, पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध मंदिर और सिद्धपीठ भी हैं. यही कारण है कि भाजपा के लिए उत्तराखंड का राजनीतिक महत्व बड़ा है. यहां से जाने वाला संदेश पूरे देश में जाता ही है, विदेश में भी इसकी गूंज सुनाई देती है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड से लगाव जगजाहिर है. राजनीति में पदार्पण से पहले केदारघाटी उनकी साधना स्थली रही है. वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की धरती और बाबा केदार के धाम के माध्यम से हिंदुत्व का संदेश देशभर में पहुंचाते रहे हैं. बाबा केदार के प्रति उनकी गहरी आस्था केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों में उनकी गहरी रुचि के रूप में सामने आई है.

केंद्र सरकार केदारनाथ के साथ ही बदरीनाथ को स्प्रिचुअल हिल सिटी के रूप में विकसित करने की योजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है. साथ में चारधाम के विकास को प्राथमिकता दी गई है.

केदारनाथ की सीट पर कब्जा जमाने की कोशिश

वहीं, कांग्रेस की रणनीति बदरीनाथ के साथ केदारनाथ की सीट पर कब्जा जमाने की है, ताकि इसके माध्यम से भाजपा के सनातन के एजेंडे को निशाने पर लिया जा सके. कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने उत्तराखंड में अपने दूसरे चुनावी दौरे में इसी कारण चमोली के साथ रुद्रप्रयाग जिलों को प्राथमिकता दी है. इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनका मनोबल बढ़ाने के साथ ही प्रदेश संगठन को भी पूरी तैयारी में जुटने को कहा जाएगा. जाहिर है, भाजपा की कोशिश जहां सनातन को लेकर आक्रामक रहने की है, वहीं कांग्रेस का प्रयास है कि भाजपा को उसकी रणनीति के साथ मात दी जाए.

भाजपा ने कांग्रेस नेता की पत्नी को टिकट देकर चौंकाया

जोगिंद्र नगर में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, क्या जीत पाएंगी बिंदु बाला?

मंडी. हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है. गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बीच मंडी जिले के जोगेंद्रनगर में राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है. भाजपा ने जिला परिषद के नेर घरबासड़ा वार्ड से कांग्रेस नेता की पत्नी को टिकट देकर सभी को चौंका दिया.

जानकारी के अनुसार, नेर घरबासड़ा वार्ड से बिंदु बाला को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है और वह अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी की पत्नी हैं. अनिल चौधरी सुक्खू सरकार में सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के पद कार्यरत हैं. बताया जा रहा है कि अनिल चौधरी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान से ही कांग्रेस के कट्टर समर्थक रहे हैं और वह पार्टी की ओर से पत्नी के लिए टिकट भी चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया. फिलहाल, कांग्रेस की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. उधर, जानकारों का मानना है कि भाजपा ने कांग्रेस में सेंधमारी करते हुए चुनावी समीकरणों को बदलने का दांव खेला है. हालांकि, चुनावी नतीजे भाजपा के दांव पर मुहर लगाएंगे कि यह कितना सफल रहा.

उधर, जोगेंद्रनगर से भाजपा विधायक प्रकाश राणा ने भाजपा प्रत्याशी के साथ तस्वीरें शेयर की और जिला परिषद के तीनों वार्डों के प्रत्याशियों को शुभकामना दी है. विधायक का दावा है कि तीनों पार्टी प्रत्याशियों की भारी बहुमत से जीत निश्चित है. गौर रहे कि इस बार भाजपा ने पार्टी संबल पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है.

विधायक राणा ने क्या कहा?

विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि जोगिंदरनगर के नेर घरवासडा वार्ड से भाजपा समर्पित प्रत्याशी बिंदु बाला जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं. कांग्रेस छोड़कर भाजपा परिवार में शामिल हुए सभी साथियों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सभी राष्ट्रहित, विकास और जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे.

बंगाल के इनाम में मंगल पांडेय को मिली विदाई

पटना. बिहार प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और नीतीश कुमार की पिछली कई सरकारों में मंत्री रहे मंगल पांडेय को इस बार सरकार में जगह नहीं मिली है. भाजपा कोटे से मंत्री बनने वाले लोगों में उनका नाम सबसे पक्का माना जा रहा था.

वे भाजपा आलाकमान के करीबी रहे हैं और दूसरी खास बात यह है कि जहां भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है उसे सफलतापूर्वक पूरा करते रहे हैं. वे पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे. हो सकता है कि चुनाव लड़ाने में उनसे ज्यादा भूमिका सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव ने निभाई हो लेकिन कई सालों से पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडेय ही थे.

तभी माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली बड़ी जीत का इनाम मंगल पांडेय को भी मिलेगा. लेकिन उलटे वे सरकार से बाहर हो गए. वे पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे और कामकाज को लेकर भी ज्यादा शिकायत नहीं थी.

विशेष | **बंगाल वाला फॉर्मूला कैसे मास्टरस्ट्रोक?**

5 ब्रह्मास्त्र से यूपी फिर जीतेगी बीजेपी!

लखनऊ. पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपार सफलता मिलने से उत्साहित बीजेपी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी वही रणनीति अपनाएगी जो उसने बंगाल में अपनाई थी. बीजेपी यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत और सक्रिय करने के बड़े इलेक्शन प्लान पर काम कर रही है.

उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी इस योजना को 1.6 लाख बूथ स्तरीय समितियों कि जरिए अंजाम देगी. बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग 80,000 बूथों को मैनेज करने की बेहद सटीक रणनीति अपनाई थी. उसने इस रणनीति के दम पर बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की. अब वह यूपी में इसी रणनीति को दोहराना चाहती है. बंगाल में बीजेपी का प्लान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और माहिर रणनीतिकार सुनील बंसल ने तैयार किया था. सुनील बंसल को सन 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मिली जीत का मुख्य सूत्रधार माना जाता है. बंसल उस समय पार्टी के यूपी के प्रभारी थे. अमित शाह ने उनके साथ मिलकर चुनाव की रणनीति बनाई थी. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई बूथ स्तर की कमेटियों के सत्यापन के काम में जुटी है. इन कमेटियों का हाल ही में संगठनात्मक फेरबदल के तहत पुनर्गठन किया गया था. यूपी बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी आलाकमान से हरी झंडी मिलने के बाद बूथ स्तर की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, इस योजना में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की केंद्र व राज्य सरकारों की उपलब्धियों को प्रचारित किया जाएगा. दूसरी तरफ विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस की कमियों को बेनकाब किया जाएगा. बीजेपी महिलाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए विपक्ष की महिला विरोधी मंशा उजागर करेगी. यानी वह लोगों को बताएगी कि विपक्ष ने कैसे महिलाओं को आरक्षण देने वाले संवैधानिक विधेयक को रोकने की कोशिश की थी.

इसके अलावा पार्टी विपक्ष के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वाले नैरेटिव का मुकाबला करने पर देने की योजना बना रही है. इस नैरेटिव ने उत्तर प्रदेश में साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था. ऐसा करने के लिए बीजेपी एक दोहरी रणनीति अपनाएगी, जिसमें योगी सरकार के कामकाज की तुलना अखिलेश यादव की पिछली सरकार के कामकाज से की जाएगी.

बीजेपी की बहु स्तरीय चुनावी रणनीति

जानकारों का कहना है कि यूपी में अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद बीजेपी निश्चिंत होकर बैठने वाली नहीं है. वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लगातार बढ़ती आक्रामकता के बीच खुद को ज्यादा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल के लिए तैयारी कर रही है. सूत्रों के अनसार, पार्टी अपनी च3 एसज की रणनीति- च्संगठनज, सरकार और संघ को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है. इसे एक बहु स्तरीय चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें राजनीतिक लामबंदी, शासन का नैरेटिव और वैचारिक मजबूती, ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे.